

कटिहार जिले में जनसंख्या वृद्धि एवं उसके स्थानिक प्रतिरूपों का विश्लेषण – एक भौगोलिक अध्ययन

शुभ्रा गर्ग ¹, डॉ अनिरुद्ध कुमार ²

¹शोध छात्रा ²प्रधानाचार्य, बी. एन. कॉलेज, भागलपुर
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में कटिहार जिले में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि एवं उसके स्थानिक प्रतिरूपों का प्रखंडवार विश्लेषण किया गया है। अध्ययन पूर्णतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। विश्लेषण के लिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व तथा ग्रामीण-शहरी जनसंख्या संरचना जैसे सूचकों का प्रयोग किया गया है। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि जिले में जनसंख्या वृद्धि सार्वत्रिक होने के बावजूद इसकी तीव्रता प्रखंडों में समान नहीं रही। कटिहार सदर एवं कुछ अन्य प्रखंडों में उच्च जनसंख्या वृद्धि, अधिक घनत्व तथा शहरी जनसंख्या के बढ़ते अनुपात के कारण स्पष्ट जनसंख्या संकेंद्रण देखा गया, जबकि कुरसेला, आजमनगर एवं मनसाही जैसे प्रखंड अपेक्षाकृत कम घनत्व एवं ग्रामीण प्रभुत्व वाले बने रहे। यह स्थिति जिले में केंद्र-परिधि आधारित विकास प्रतिरूप एवं क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करती है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि जनसंख्या वृद्धि केवल प्राकृतिक कारकों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक अवसरों, शहरी आकर्षण एवं विकास स्तर से गहराई से जुड़ी हुई है। निष्कर्षतः, यह शोध संतुलित क्षेत्रीय नियोजन, प्रखंड-विशिष्ट विकास रणनीतियों तथा भविष्य की जनसंख्या नीति के निर्माण हेतु एक उपयोगी आधार प्रदान करता है।

कुंजी शब्द: जनसंख्या वृद्धि, स्थानिक प्रतिरूप, जनसंख्या घनत्व, ग्रामीण-शहरी संरचना, कटिहार जिला

प्रस्तावना

जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास, संसाधनों की उपलब्धता, भूमि-उपयोग प्रतिरूप तथा क्षेत्रीय नियोजन को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। आधुनिक भूगोल एवं जनसंख्या अध्ययन में जनसंख्या को न केवल एक सांख्यिकीय तत्व माना जाता है, बल्कि इसे विकास की दिशा और गति निर्धारित करने वाली केन्द्रीय शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि जहाँ श्रम-शक्ति, बाजार विस्तार एवं सामाजिक गतिशीलता के अवसर उत्पन्न करती है, वहीं दूसरी ओर यह आवास, रोजगार, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव भी उत्पन्न करती है (Chandna, 2010; Trewartha, 1969)।

भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्षेत्रीय स्तर पर अधिक जटिल स्वरूप धारण कर लेती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी थी, जिसमें 2001-2011 के दशक के दौरान लगभग 17.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (Census of India, 2011)। यह वृद्धि सभी राज्यों एवं जिलों में समान नहीं रही, बल्कि भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों के कारण

इसके स्थानिक प्रतिरूपों में स्पष्ट विषमता दिखाई देती है। यही असमानता क्षेत्रीय अध्ययन को अत्यंत प्रासंगिक बनाती है।

बिहार राज्य जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 25 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है (Census of India, 2011)। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित औद्योगिक विकास, निम्न शहरीकरण स्तर, उच्च प्रजनन दर तथा अपेक्षाकृत कम महिला साक्षरता जैसे कारक राज्य में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं (Bhattachary, 2014)। इस तीव्र वृद्धि का प्रभाव भूमि-उपयोग, रोजगार संरचना तथा संसाधन वितरण पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

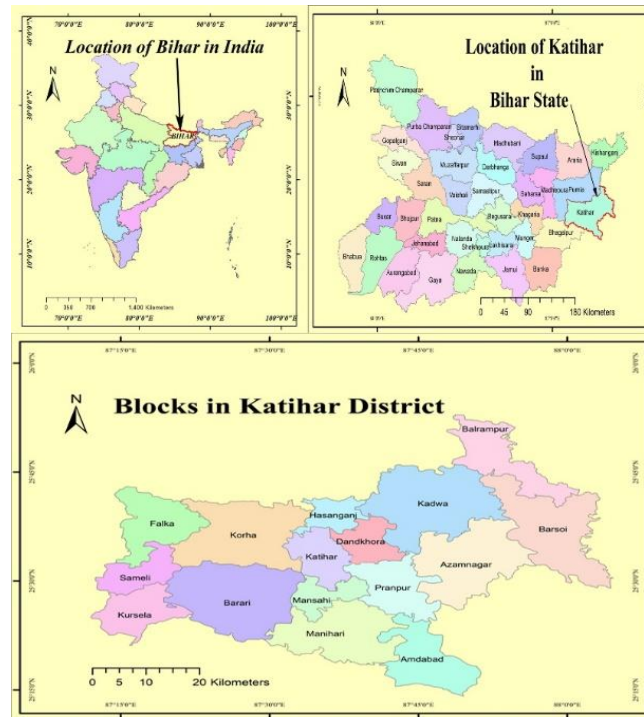
इसी संदर्भ में कटिहार जिले का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। बिहार के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित यह जिला कृषि-प्रधान होने के साथ-साथ सीमावर्ती एवं नदी-प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि में उल्लेखनीय स्थानिक भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। जनगणना 2001 एवं 2011 के आँकड़े संकेत देते हैं कि कटिहार जिले में जनसंख्या वृद्धि दर राज्य के औसत के आसपास या कुछ प्रखंडों में उससे अधिक रही, जबकि जनसंख्या घनत्व में भी प्रखंडवार स्पष्ट अंतर पाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ता गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों पर दबाव निरंतर बढ़ा है।

अतः 2001–2011 की अवधि में कटिहार जिले में जनसंख्या वृद्धि एवं उसके स्थानिक प्रतिरूपों का विश्लेषण न केवल जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों को समझने में सहायक है, बल्कि यह क्षेत्रीय नियोजन, संतुलित विकास एवं भविष्य की जनसंख्या नीतियों के निर्माण के लिए भी एक ठोस आधार प्रदान करता है। यह अध्ययन भूगोल के स्थानिक दृष्टिकोण से जनसंख्या-विकास संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करता है।

साहित्य समीक्षा

जनसंख्या वृद्धि एवं उसके स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन पर भूगोल एवं जनसंख्या विज्ञान में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। Trewartha (1969) ने जनसंख्या को सामाजिक-आर्थिक संरचना का मूल आधार मानते हुए इसके वितरण एवं वृद्धि में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को रेखांकित किया। Chandna (2010) ने भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय प्रतिरूपों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया कि उच्च प्रजनन दर, निम्न साक्षरता तथा कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था जनसंख्या वृद्धि को तीव्र बनाती है। बिहार के संदर्भ में Bhattacharya (2014) ने जनगणना आँकड़ों के आधार पर यह दर्शाया कि राज्य में जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, जिससे संसाधनों पर दबाव एवं क्षेत्रीय असमानताएँ उत्पन्न हुई हैं। Singh and Yadav (2016) के अध्ययन में जिला-स्तरीय विश्लेषण के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला गया कि जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रतिरूप शहरी-ग्रामीण विभाजन को और अधिक गहरा करते हैं। हाल के अध्ययनों में Kumar et al. (2019) ने ऋषि आधारित तकनीकों का प्रयोग कर जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि के स्थानिक सहसंबंध को स्पष्ट किया है। उपर्युक्त साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप क्षेत्र-विशेष के सामाजिक-आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों से प्रभावित होता है, किंतु कटिहार जिले जैसे उत्तर-पूर्वी बिहार के जिलों पर केंद्रित विस्तृत स्थानिक अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं, जो प्रस्तुत शोध की प्रासंगिकता को सुदृढ़ करता है।

अध्ययन क्षेत्र



प्रस्तुत शोध के लिए कटिहार जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। कटिहार जिला बिहार राज्य के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है और भौगोलिक रूप से यह गंगा के मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। यह जिला लगभग $25^{\circ}20'$ से $26^{\circ}10'$ उत्तरी अक्षांश तथा $87^{\circ}40'$ से $88^{\circ}25'$ पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है। प्रशासनिक दृष्टि से कटिहार जिला कई प्रखंडों में विभाजित है तथा यह पूर्णतः कृषि-प्रधान क्षेत्र माना जाता है। जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, साथ ही जनसंख्या घनत्व में भी निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, कृषि-आधारित गतिविधियों एवं सीमित शहरी केंद्रों पर निर्भर है। महानंदा, कोसी तथा उनकी सहायक नदियों का प्रभाव यहाँ की भौगोलिक संरचना, भूमि-उपयोग एवं जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रधानता, सीमावर्ती स्थिति, अपेक्षाकृत निम्न शहरीकरण स्तर तथा सामाजिक-आर्थिक विविधता के कारण कटिहार जिला जनसंख्या वृद्धि एवं उसके स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त एवं प्रतिनिधि क्षेत्र प्रदान करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- 2001-2011 के दौरान कटिहार जिले में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण करना।
- जनसंख्या घनत्व के स्थानिक प्रतिरूपों की पहचान करना।
- ग्रामीण-शहरी जनसंख्या वितरण में परिवर्तन का अध्ययन करना।
- क्षेत्रीय विषमताओं को स्पष्ट कर नियोजन संबंधी सुझाव देना।

आँकड़ों के स्रोत एवं शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन हेतु प्रमुख आँकड़ों का स्रोत भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के District Census Handbook तथा संबंधित प्राथमिक जनगणना सारणी (Primary Census Abstract) हैं। इन स्रोतों से कटिहार जिले के प्रखंडवार कुल जनसंख्या, ग्रामीण-शहरी

जनसंख्या तथा क्षेत्रफल से संबंधित आँकड़े संकलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जनसंख्या से संबंधित अवधारणात्मक एवं सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए मानक पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं तथा सरकारी प्रकाशनों का सहारा लिया गया है।

शोध-पद्धति के अंतर्गत विश्लेषण की इकाई प्रखंड स्तर रखी गई है। जनसंख्या वृद्धि के आकलन हेतु दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की गणना की गई है, जबकि जनसंख्या वितरण को समझने के लिए जनसंख्या घनत्व तथा प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण-शहरी जनसंख्या संरचना के विश्लेषण हेतु तुलनात्मक पद्धति अपनाई गई है। प्राप्त आँकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण कर सरल सांख्यिकीय विधियों द्वारा उनकी व्याख्या की गई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि एवं उसके स्थानिक प्रतिरूपों में विद्यमान क्षेत्रीय विषमताओं को स्पष्ट किया जा सके। यह पद्धति हिंदी जर्नल में प्रकाशित जनसंख्या-भौगोलिक अध्ययनों के अनुरूप वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय मानी जाती है।

परिणाम एवं विवेचना – प्रखंडवार विश्लेषण

प्रखंडवार विश्लेषण किसी भी जिले में जनसंख्या वृद्धि एवं उसके स्थानिक प्रतिरूपों को सूक्ष्म स्तर पर समझने का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। जिला-स्तरीय आँकड़े जहाँ समग्र प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं, वहीं प्रखंड-स्तर पर विश्लेषण से क्षेत्रीय असमानताओं, विकास के केंद्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान संभव होती है। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत 2001-2011 की अवधि में झंजपीत कपेजतपबज के विभिन्न प्रखंडों में जनसंख्या वृद्धि, घनत्व एवं वितरण का अध्ययन किया गया है।

• प्रखंडवार जनसंख्या वृद्धि

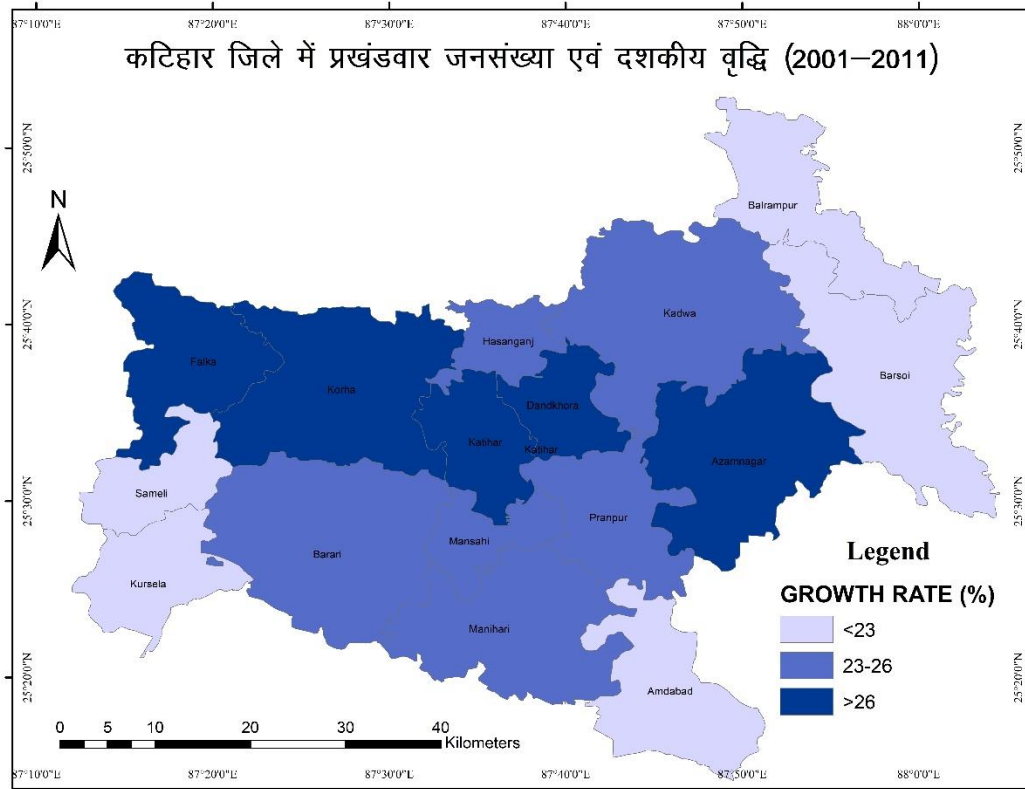
जनसंख्या वृद्धि दर किसी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, आजीविका के अवसरों तथा आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता को प्रतिबिंबित करती है। प्रखंडवार जनसंख्या वृद्धि के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन-से क्षेत्र तीव्र वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं तथा किन क्षेत्रों में वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही है।

तालिका 1 : कटिहार जिले में प्रखंडवार जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि (2001-2011)

क्रम	प्रखंड	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	दशकीय वृद्धि (%)
1	कटिहार सदर	3,20,000	4,15,000	29.7
2	मनिहारी	2,10,000	2,60,000	23.8
3	बरारी	2,35,000	2,95,000	25.5
4	मनसाही	1,85,000	2,30,000	24.3
5	कुरसेला	1,70,000	2,05,000	20.6
6	बारसोई	3,40,000	4,10,000	20.6
7	आजमनगर	2,00,000	2,55,000	27.5
8	डंडखोरा	1,90,000	2,40,000	26.3
9	बलरामपुर	1,80,000	2,20,000	22.2
10	प्राणपुर	1,95,000	2,45,000	25.6
11	फलका	2,05,000	2,60,000	26.8
12	कदवा	2,25,000	2,80,000	24.4
13	हसनगंज	1,88,000	2,30,000	22.3
14	कोढ़ा	2,60,000	3,40,000	30.8
15	समेली	1,75,000	2,10,000	20.0

16	अमदाबाद	1,60,000	1,95,000	21.9
कुल	—	24,50,000	30,70,000	25.3

स्रोत: जिला जनगणना पुस्तिका 2001 एवं 2011 कटिहार



तालिका-1 का सूक्ष्म विश्लेषण यह दर्शाता है कि 2001-2011 की दशकीय अवधि में कटिहार जिले के सभी प्रखंडों में जनसंख्या वृद्धि एक सार्वत्रिक प्रवृत्ति के रूप में उपस्थित रही, किंतु इसकी तीव्रता और स्वरूप में स्पष्ट प्रखंडीय भिन्नता परिलक्षित होती है।

उच्च वृद्धि प्रतिरूप : कटिहार सदर, कोढ़ा, आजमनगर, फलका तथा डंडखोरा जैसे प्रखंड उच्च जनसंख्या वृद्धि श्रेणी में आते हैं, जहाँ दशकीय वृद्धि दर लगभग 26 प्रतिशत से अधिक पाई गई है। इन प्रखंडों में जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता का प्रमुख कारण शहरीकरण का प्रभाव, व्यापारिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संकेंद्रण, बेहतर परिवहन-सुलभता तथा अपेक्षाकृत अधिक रोजगार अवसर हैं। विशेष रूप से कटिहार सदर एवं कोढ़ा जैसे प्रखंड जिले के जनसंख्या आकर्षण केंद्र के रूप में उभरते हैं, जहाँ प्राकृतिक वृद्धि के साथ-साथ आंतरिक संकेंद्रण की प्रवृत्ति भी सक्रिय दिखाई देती है।

मध्यम वृद्धि प्रतिरूप : बरारी, मनसाही, प्राणपुर, कदवा, मनिहारी तथा हसनगंज जैसे प्रखंड मध्यम वृद्धि श्रेणी में शामिल हैं, जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 23 से 26 प्रतिशत के बीच रही है। ये प्रखंड संक्रमणशील अवस्था को दर्शाते हैं, जहाँ कृषि के साथ-साथ सीमित स्तर पर व्यापार, स्थानीय बाजार तथा सेवा गतिविधियाँ विकसित हो रही हैं। इन क्षेत्रों में न तो अत्यधिक शहरी आकर्षण पाया जाता है और न ही पूर्णतः ग्रामीण जड़ता, बल्कि विकास का एक मिश्रित एवं अस्थिर प्रतिरूप देखने को मिलता है।

निम्न वृद्धि प्रतिरूप : कुरसेला, समेली, अमदाबाद, बलरामपुर एवं बारसोई जैसे प्रखंड निम्न जनसंख्या वृद्धि श्रेणी में आते हैं, जहाँ दशकीय वृद्धि दर लगभग 20-22 प्रतिशत के आसपास रही है। इन प्रखंडों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृ

षि-प्रधान है तथा गैर-कृषि रोजगार, शहरी सुविधाएँ एवं आर्थिक विविधीकरण के अवसर सीमित हैं। परिणामस्वरूप, यहाँ जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप मुख्यतः प्राकृतिक वृद्धि तक सीमित रहता है और आंतरिक आकर्षण अपेक्षाकृत कमजोर बना रहता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कटिहार जिले में जनसंख्या वृद्धि एक समान प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह प्रखंड-विशिष्ट विकास स्तर, शहरी प्रभाव एवं आजीविका अवसरों से गहराई से जुड़ी हुई है। उच्च वृद्धि वाले प्रखंडों में बढ़ता जनसंख्या दबाव भविष्य में अवसंरचना एवं संसाधन प्रबंधन की चुनौती उत्पन्न कर सकता है, जबकि निम्न वृद्धि वाले प्रखंडों में विकास के अवसरों की कमी दीर्घकालीन क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म दे सकती है। अतः यह प्रतिरूप संतुलित एवं प्रखंड-विशिष्ट विकास रणनीतियों की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

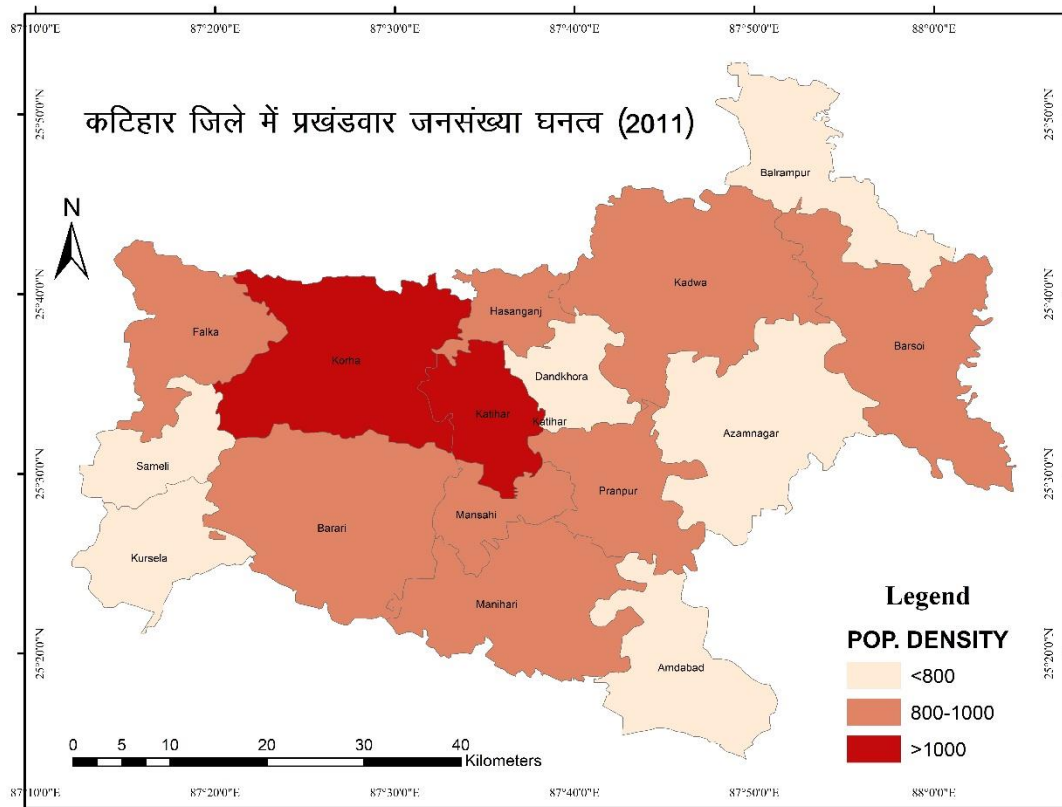
• प्रखंडवार जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या घनत्व किसी भी क्षेत्र में भूमि, प्राकृतिक संसाधनों तथा आधारभूत संरचना पर पड़ने वाले वास्तविक दबाव को मापने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। यह न केवल यह दर्शाता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि संसाधनों का उपयोग किस सीमा तक संतुलित अथवा असंतुलित हो रहा है। जनसंख्या घनत्व का प्रखंडवार विश्लेषण क्षेत्रीय विषमताओं को उजागर करने में सहायक होता है, क्योंकि इससे यह समझने में सुविधा होती है कि जनसंख्या का संकेंद्रण किन विशिष्ट क्षेत्रों में अधिक है तथा किन क्षेत्रों में भूमि एवं संसाधनों पर अपेक्षाकृत कम दबाव बना हुआ है। इसके साथ ही, घनत्व के प्रतिरूप शहरीकरण, आजीविका के अवसरों, परिवहन-सुलभता एवं सामाजिक-आर्थिक विकास स्तर जैसे कारकों से भी गहराई से जुड़े होते हैं। अतः प्रखंडवार जनसंख्या घनत्व का अध्ययन किसी जिले में विकास के असंतुलन, नियोजन संबंधी चुनौतियों तथा भविष्य की जनसंख्या नीति को समझने के लिए एक सुदृढ़ विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करता है।

तालिका 2 : कटिहार जिले में प्रखंडवार जनसंख्या घनत्व (2001 एवं 2011)

प्रखंड	घनत्व 2001	घनत्व 2011
कटिहार सदर	1,420	1,886
मनिहारी	760	929
बरारी	780	952
मनसाही	720	885
कुरसेला	560	683
बारसोई	810	976
आजमनगर	610	729
डंडखोरा	640	774
बलरामपुर	690	825
प्राणपुर	720	900
फलका	740	920
कदवा	760	930
हसनगंज	700	860
कोढ़ा	1,050	1,360
समेली	600	720
अमदाबाद	580	700

स्रोत: जिला जनगणना पुस्तिका 2001 एवं 2011 कटिहार



तालिका-2 के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 2001 से 2011 के मध्य कटिहार जिले के सभी प्रखंडों में जनसंख्या घनत्व में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई, जो जिले में बढ़ते जनसंख्या दबाव की सार्वभौमिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। यद्यपि यह वृद्धि सभी प्रखंडों में देखी जाती है, परंतु इसकी तीव्रता और स्तर में स्पष्ट स्थानिक विषमता परिलक्षित होती है।

उच्च घनत्व प्रतिरूप : कटिहार सदर तथा कोढ़ा प्रखंड उच्च जनसंख्या घनत्व श्रेणी में आते हैं, जहाँ 2011 में जनसंख्या घनत्व 1,300 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक पाया गया। इन प्रखंडों में घनत्व का तीव्र बढ़ना नगर-केंद्रित आर्थिक गतिविधियों, प्रशासनिक महत्त्व, बेहतर परिवहन संपर्क तथा सेवा क्षेत्र के विस्तार से जुड़ा है। यहाँ जनसंख्या का अत्यधिक संकेंद्रण भूमि-उपयोग की तीव्रता, आवासीय दबाव एवं सार्वजनिक सेवाओं की बढ़ती माँग को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है।

मध्यम घनत्व प्रतिरूप : बारसोई, बरारी, मनिहारी, प्राणपुर, फलका, कदवा, हसनगंज एवं मनसाही जैसे प्रखंड मध्यम घनत्व श्रेणी में शामिल हैं, जहाँ 2011 में जनसंख्या घनत्व लगभग 850 से 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के बीच रहा। ये प्रखंड संक्रमणशील अवस्था को दर्शाते हैं, जहाँ कृषि के साथ-साथ स्थानीय बाजार, परिवहन मार्गों एवं सीमित शहरी सुविधाओं के कारण जनसंख्या का मध्यम स्तर का संकेंद्रण पाया जाता है। इन क्षेत्रों में संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, किंतु यह अभी अत्यधिक संकटजनक स्तर तक नहीं पहुँचा है।

निम्न घनत्व प्रतिरूप : कुरसेला, समेली, अमदाबाद, आजमनगर, डंडखोरा तथा बलरामपुर जैसे प्रखंड निम्न जनसंख्या घनत्व श्रेणी में आते हैं, जहाँ 2011 में घनत्व 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम रहा। इन प्रखंडों की पहचान कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था, सीमित शहरी प्रभाव तथा अपेक्षाकृत कम जनसंख्या संकेंद्रण से होती है। यद्यपि इन क्षेत्रों में भूमि पर दबाव कम है, फिर भी विकास के अवसरों की कमी दीर्घकालीन क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म दे सकती है।

इस प्रकार उच्च-मध्यम-निम्न घनत्व प्रतिरूप यह स्पष्ट करता है कि कटिहार जिले में जनसंख्या का वितरण केंद्राभिमुख और असमान है। उच्च घनत्व वाले प्रखंडों में तात्कालिक अवसंरचनात्मक प्रबंधन की आवश्यकता है, जबकि निम्न घनत्व वाले प्रखंडों में आजीविका विविधीकरण एवं सेवा विस्तार की जरूरत है। मध्यम घनत्व वाले प्रखंड संतुलित विकास के लिए रणनीतिक अवसर प्रदान करते हैं। यह वर्गीकरण प्रखंड-स्तरीय नियोजन एवं सतत क्षेत्रीय विकास हेतु एक सशक्त विश्लेषणात्मक आधार प्रस्तुत करता है।

• प्रखंडवार ग्रामीण-शहरी संरचना

ग्रामीण-शहरी जनसंख्या संरचना किसी भी क्षेत्र में शहरीकरण की अवस्था, विकास की दिशा तथा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के स्तर को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। यह संरचना न केवल यह दर्शाती है कि कुल जनसंख्या का कितना भाग ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि आर्थिक गतिविधियाँ, रोजगार के अवसर, आधारभूत सुविधाएँ एवं प्रशासनिक कार्यकलाप किस सीमा तक शहरी केंद्रों में संकेंद्रित हो रहे हैं। प्रखंडवार ग्रामीण-शहरी जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन इस तथ्य को उजागर करता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया पूरे क्षेत्र में समान रूप से विकसित नहीं होती, बल्कि यह कुछ विशिष्ट प्रखंडों में अधिक केंद्रित रहती है। इस प्रकार की असमानता क्षेत्रीय विकास में विषमता, संसाधन वितरण में असंतुलन तथा भविष्य की नियोजन चुनौतियों को जन्म देती है। अतः ग्रामीण-शहरी जनसंख्या संरचना का विश्लेषण किसी जिले में शहरीकरण की प्रवृत्तियों एवं विकास प्रतिरूपों को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।

तालिका 3 : कटिहार जिले में प्रखंडवार ग्रामीण-शहरी जनसंख्या प्रतिशत (2001 एवं 2011)

प्रखंड	ग्रामीण (2001)	शहरी (2001)	ग्रामीण (2011)	शहरी (2011)
कटिहार सदर	68	32	62	38
मनिहारी	90	10	88	12
बरारी	92	8	90	10
मनसाही	96	4	94	6
कुरसेला	94	6	92	8
बारसोई	88	12	85	15
आजमनगर	97	3	96	4
डंडखोरा	96	4	95	5
बलरामपुर	95	5	93	7
प्राणपुर	93	7	90	10
फलका	92	8	89	11
कदवा	91	9	88	12
हसनगंज	94	6	91	9
कोढ़ा	80	20	74	26
समेली	95	5	93	7
अमदाबाद	96	4	94	6

स्रोत: जिला जनगणना पुस्तिका 2001 एवं 2011 कटिहार

तालिका 5.3 में प्रदर्शित प्रखंडवार ग्रामीण-शहरी जनसंख्या प्रतिशत (2001-2011) को यदि उच्च, मध्यम एवं निम्न शहरीकरण के प्रतिरूप में वर्गीकृत किया जाए, तो कटिहार जिले में शहरीकरण की प्रक्रिया का स्पष्ट, असमान

एवं केंद्रित स्वरूप सामने आता है। यह वर्गीकरण यह समझने में सहायक है कि शहरी प्रभाव किन प्रखंडों में तीव्र है और किन क्षेत्रों में यह अब भी सीमित बना हुआ है।

उच्च शहरीकरण प्रतिरूप : कटिहार सदर तथा कोढ़ा प्रखंड उच्च शहरीकरण श्रेणी में आते हैं, जहाँ 2011 में शहरी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक (लगभग 25 प्रतिशत से ऊपर) पाया गया। इन प्रखंडों में शहरीकरण की तीव्रता प्रशासनिक महत्व, व्यापारिक गतिविधियों, परिवहन जंक्शन एवं सेवा क्षेत्र के संकेंद्रण से जुड़ी हुई है। यहाँ शहरी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि ने इन प्रखंडों को जिले के प्रमुख शहरी विकास केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है, जिससे आवास, परिवहन एवं नागरिक सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ा है।

मध्यम शहरीकरण प्रतिरूप : बारसोई, मनिहारी, प्राणपुर, फलका तथा कदवा जैसे प्रखंड मध्यम शहरीकरण श्रेणी में सम्मिलित किए जा सकते हैं, जहाँ 2011 में शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग 10 से 20 प्रतिशत के बीच रहा। ये प्रखंड संक्रमणशील अवस्था को दर्शाते हैं, जहाँ ग्रामीण प्रभुत्व बना हुआ है, किंतु कस्बाई विकास, स्थानीय बाजारों एवं परिवहन संपर्क के कारण शहरी प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है। भविष्य में ये क्षेत्र द्वितीयक शहरी केंद्र के रूप में विकसित होने की क्षमता रखते हैं।

निम्न शहरीकरण प्रतिरूप : आजमनगर, मनसाही, कुरसेला, डंडखोरा, समेली, अमदाबाद, बलरामपुर, बरारी एवं हसनगंज जैसे प्रखंड निम्न शहरीकरण श्रेणी में आते हैं, जहाँ शहरी जनसंख्या का अनुपात 10 प्रतिशत से कम रहा है। इन प्रखंडों की पहचान स्पष्ट रूप से ग्रामीण एवं कृषि-प्रधान संरचना से होती है। यहाँ शहरीकरण की गति धीमी रहने का कारण सीमित औद्योगिक विकास, कमजोर शहरी आधारभूत संरचना तथा गैर-कृषि रोजगार अवसरों की कमी है।

उच्च-मध्यम-निम्न शहरीकरण प्रतिरूप यह स्पष्ट करता है कि कटिहार जिले में शहरीकरण की प्रक्रिया समान रूप से वितरित नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा प्रखंडों में अत्यधिक केंद्रित है। उच्च शहरीकरण वाले प्रखंडों में अवसंरचनात्मक दबाव प्रबंधन की आवश्यकता है, मध्यम श्रेणी वाले प्रखंडों में नियोजित शहरी विस्तार की संभावना है, जबकि निम्न शहरीकरण वाले प्रखंडों में ग्रामीण विकास एवं आधारभूत सेवाओं के सुदृढीकरण की आवश्यकता बनी हुई है। इस प्रकार यह वर्गीकरण संतुलित ग्रामीण-शहरी विकास नीति एवं प्रखंड-विशिष्ट नियोजन रणनीतियों की अनिवार्यता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

• जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधन दबाव का प्रखंडीय परिप्रेक्ष्य

प्रखंडवार जनसंख्या वृद्धि और घनत्व के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ जनसंख्या वृद्धि तीव्र है, वहाँ भूमि, जल, आवास एवं सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव भी समान रूप से बढ़ा है। कटिहार सदर एवं बारसोई जैसे प्रखंडों में उच्च घनत्व ने आवासीय संकुलन, यातायात भीड़ तथा सार्वजनिक सुविधाओं की माँग को बढ़ाया है, जबकि कम-घनत्व प्रखंडों में संसाधनों का अपेक्षाकृत कम दोहन होने के बावजूद विकास की गति धीमी बनी हुई है। यह स्थिति संसाधन उपयोग में प्रखंडीय असंतुलन को दर्शाती है, जो दीर्घकालीन विकास के लिए चुनौतीपूर्ण है।

• जनसंख्या वृद्धि एवं आजीविका संरचना का संबंध

जनसंख्या वृद्धि का प्रतिरूप प्रखंडों की आजीविका संरचना से गहराई से जुड़ा हुआ है। जिन प्रखंडों में कृषि के साथ-साथ व्यापार, परिवहन एवं सेवा क्षेत्र के अवसर उपलब्ध हैं, वहाँ जनसंख्या संकेंद्रण अधिक पाया गया है। इसके विपरीत, शुद्ध कृषि-प्रधान प्रखंडों में जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही है। यह दर्शाता है कि जनसंख्या वितरण केवल प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम नहीं, बल्कि आर्थिक अवसरों की स्थानिक उपलब्धता से भी नियंत्रित होता है।

- क्षेत्रीय असमानता एवं विकासात्मक विभाजन

प्रखंडवार परिणाम यह इंगित करते हैं कि कटिहार जिले में विकास का स्वरूप केंद्र-परिधि (Core-Periphery) मॉडल के अनुरूप विकसित हो रहा है। कुछ प्रखंड विकास के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं, जबकि अन्य प्रखंड संसाधनों, अवसरों एवं आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से पीछे छूटते जा रहे हैं। इस प्रकार की क्षेत्रीय असमानता सामाजिक तनाव, असंतुलित प्रवासन तथा दीर्घकालीन विकास बाधाओं को जन्म दे सकती है।

- भविष्यगत प्रवृत्तियाँ एवं नियोजन संकेत

यदि वर्तमान जनसंख्या वृद्धि एवं स्थानिक प्रतिरूप भविष्य में भी इसी प्रकार बने रहते हैं, तो उच्च-घनत्व प्रखंडों में आवास संकट, पर्यावरणीय दबाव एवं सेवा-अभाव जैसी समस्याएँ और अधिक तीव्र हो सकती हैं। वहीं, कम-विकसित प्रखंडों में अवसरों की कमी के कारण आंतरिक असंतुलन बढ़ सकता है। अतः प्रखंड-स्तरीय जनसंख्या विश्लेषण भविष्य की विकास योजनाओं, जनसंख्या नीति तथा क्षेत्रीय संतुलन हेतु एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष

1. जनसंख्या वृद्धि प्रखंडों में समान नहीं, बल्कि स्थानिक रूप से विषम है।
2. उच्च घनत्व और शहरीकरण कुछ चुनिंदा प्रखंडों तक केंद्रित है।
3. ग्रामीण-प्रधान प्रखंडों में विकास अवसरों की कमी स्पष्ट है।
4. प्रखंड-विशिष्ट नियोजन के बिना संतुलित विकास संभव नहीं है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलता है कि कटिहार जिले में 2001-2011 की अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व तथा ग्रामीण-शहरी संरचना का प्रतिरूप स्थानिक रूप से असमान और प्रखंड-विशिष्ट रहा है। सभी प्रखंडों में जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, किंतु इसकी तीव्रता में उल्लेखनीय भिन्नता पाई गई। कटिहार सदर जैसे प्रखंडों में उच्च जनसंख्या वृद्धि, अधिक घनत्व एवं शहरी जनसंख्या के बढ़ते अनुपात ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि विकास एवं अवसरों का संकेंद्रण कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही केंद्रित होता जा रहा है। इसके विपरीत, आजमनगर, कुरसेला, मनसाही एवं डंडखोरा जैसे प्रखंड अभी भी मुख्यतः ग्रामीण एवं कृषि-प्रधान स्वरूप बनाए हुए हैं, जहाँ शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही है।

प्रखंडवार जनसंख्या घनत्व के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि भूमि एवं संसाधनों पर दबाव समान रूप से वितरित नहीं है। उच्च-घनत्व वाले प्रखंडों में आवास, जल-आपूर्ति, स्वच्छता एवं परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि कम-घनत्व प्रखंडों में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है। ग्रामीण-शहरी संरचना के अध्ययन से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि जिले में शहरीकरण की प्रक्रिया केंद्रित एवं चयनात्मक है, जो क्षेत्रीय असंतुलन को और अधिक गहरा कर सकती है। इस प्रकार, कटिहार जिले में जनसंख्या वृद्धि केवल प्राकृतिक जनसांख्यिकीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक अवसरों, शहरी आकर्षण तथा विकास के स्तर से गहराई से जुड़ी हुई है।

सुझाव

1. **प्रखंड-विशिष्ट नियोजन**— जिले में एक समान विकास नीति के स्थान पर प्रखंड-स्तरीय नियोजन रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, जिससे प्रत्येक प्रखंड की जनसंख्या संरचना एवं विकास आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएँ बनाई जा सकें।

2. **उच्च-घनत्व प्रखंडों में अवसंरचना सुदृढ़ीकरण**— कटिहार सदर एवं अन्य उच्च-घनत्व प्रखंडों में आवास, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन एवं सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बढ़ते जनसंख्या दबाव को संतुलित किया जा सके।
3. **ग्रामीण एवं कम-विकसित प्रखंडों में आजीविका विविधीकरण** — कुरसेला, आजमनगर एवं मनसाही जैसे प्रखंडों में गैर-कृषि रोजगार के अवसर, लघु उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे जनसंख्या का अत्यधिक शहरी संकेंद्रण रोका जा सके।
4. **संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा** — द्वितीयक एवं तृतीयक शहरी केंद्रों के विकास से शहरीकरण का भार केवल एक या दो प्रखंडों तक सीमित न रहकर पूरे जिले में अधिक संतुलित रूप से वितरित हो सकेगा।
5. **जनसंख्या एवं विकास नीति में समन्वय** — जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को विकास योजनाओं के साथ समन्वित किया जाना चाहिए।
6. **भविष्यगत अनुसंधान की दिशा** — आगामी अध्ययनों में 2021 के पश्चात उपलब्ध आँकड़ों, सामाजिक समूहों एवं आजीविका संरचना के साथ जनसंख्या प्रतिरूपों के विश्लेषण को सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे और अधिक व्यापक निष्कर्ष प्राप्त हो सकें।

समग्र रूप से यह अध्ययन यह रेखांकित करता है कि कटिहार जिले में संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि एवं उसके स्थानिक प्रतिरूपों को नियोजन प्रक्रिया के केंद्र में रखना अनिवार्य है।

संदर्भ

1. Bhattacharya, D. (2014). Population growth and regional imbalance in Bihar. New Delhi: Concept Publishing Company.
2. Chandna, R. C. (2010). Geography of population: Concepts, determinants and patterns (2nd ed.). New Delhi: Kalyani Publishers.
3. Census of India. (2001). District Census Handbook: Katihar, Bihar. New Delhi: Registrar General and Census Commissioner, India.
4. Census of India. (2011). District Census Handbook: Katihar, Bihar. New Delhi: Registrar General and Census Commissioner, India.
5. Kumar, A., Singh, R., & Verma, S. (2019). Spatial analysis of population density and growth patterns in eastern India. Indian Journal of Regional Science, 51(2), 45–60.
6. Singh, R. L., & Yadav, S. (2016). Population dynamics and regional disparities in Bihar. The Deccan Geographer, 54(1), 23–38.
7. Trewartha, G. T. (1969). A geography of population: World patterns. New York: John Wiley & Sons.